

थानेदार व पुलिस पर मारने का शक, सीआईडी करेगी जांच

<https://www.livehindustan.com/jharkhand/ranchi/story-police-and-police-suspected-of-killing-cid-will-investigate-4018474.html>

गुमला के घाघरा पुलिस की हिरासत में कृष्णा उरांव की मौत की सीआईडी जांच होगी। 27 मार्च को घाघरा के बालमित्र थाना के कक्ष में कृष्णा उरांव का शव फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट व प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद घाघरा के तत्कालीन थानेदार कुंदन कुमार को एसपी हृदीप पी जनार्दनन ने निलंबित कर दिया था। राज्य पुलिस मुख्यालय ने मामले में सीआईडी से निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीआईडी ने केस को टेकओवर कर लिया है।

क्या है मामला

गुमला के घाघरा के घाघरापाठ में 21 अप्रैल को पांच वर्षीय अनुज उरांव की हत्या कर शव को तालाब के किनारे फेंक दिया गया था। अनुज की हत्या के बाद शव को पत्थर से ढक दिया गया था। घटना के बाद अनुज की मां के बयान पर तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, इसके बाद छोड़ दिया। वहीं 27 अप्रैल को अनुज के पिता कृष्णा को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बाल मित्र थाने के कार्यालय में कृष्णा से पूछताछ की, इसके बाद उसे बाहर से बंद कर अधिकारी चले गए। लौटने के बाद उसी शाम अधिकारियों ने पाया कि कृष्णा ने खिड़की के सहारे अपने गमछी से फांसी लगा दी है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए थे। वहीं 28 अप्रैल को थानेदार को एसपी ने निलंबित कर दिया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई है जानकारी

पुलिस हिरासत में कृष्णा उरांव की मौत की जानकारी गुमला पुलिस व मुख्यालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी है। वहीं इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी आयोग को दी गई है।

बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास

<https://www.dw.com/hi/%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%88-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8/a-57464110>

पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने दर्जनों मकान और राजनीतिक दलों के दफ्तर भी जला दिए हैं। मरने वालों में से नौ बीजेपी, सात टीएमसी और एक व्यक्ति संयुक्त मोर्चा का है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली ममता बनर्जी ने तमाम पक्षों से हिंसा पर शीघ्र अंकुश लगाने की अपील की है और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा देने का एलान किया है। लेकिन पहले दिन से ही फर्जी वीडियो और तस्वीरों के जरिए इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज किया है और कोई तीन दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस हिंसा के मामले पर टीएमसी और बीजेपी के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।

केंद्र-राज्य टकराव

केंद्र सरकार ने इस हिंसा पर पहले राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और चौबीस घंटे के भीतर रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कड़ा पत्र लिखा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर इस मामले की जानकारी ली। इसके अगले दिन ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक चार सदस्यीय टीम हिंसा का जायजा लेने कोलकाता पहुंच गई। उससे पहले बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा भी मंगलवार को दो दिन के दौरे पर बंगाल आए थे और उन्होंने हिंसा में मारे गए पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के घरवालों से मुलाकात की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस हिंसा का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है तो महिलाओं पर कथित अत्याचार के वीडियो और तस्वीरें देखने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मौके पर अपनी टीम भेजने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "केंद्र ने कभी राज्य में कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन या वैक्सीन के मामले पर कोई टीम नहीं भेजी थी। लेकिन सरकार के गठन के चौबीस घंटे के भीतर उसने हिंसा पर पत्र लिखा और केंद्रीय टीम

को बंगाल भेज दिया. केंद्रीय मंत्री भी राज्य के दौरे पर पहुंच गए. मैंने अपने राजनीतिक करियर में पहले कभी ऐसा नहीं देखा है." उनका दावा था कि बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ग्रामीण इलाकों में हिंसा उकसा रहे हैं. लेकिन सरकार दंगा भड़काने का उनका मंसूबा कामयाब नहीं होने देगी.

सोशल मीडिया पर तस्वीरें

फेसबुक और ट्विटर पर तमाम ऐसे वीडियो और तस्वीरें हैं जिनको इस हिंसा से संबंधित बताया जा रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हिंसा की घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराने का प्रयास कर रही है. उनका कहना था, "राज्य में चुनाव बाद हिंसा की कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं. लेकिन बीजेपी इस आग में घी डालने का प्रयास कर रही है. हिंसा उन इलाकों में ज्यादा हो रही है जहां बीजेपी जीती है. इस हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें भी हो रही हैं. इसके लिए फर्जी वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे." ममता का कहना है कि चुनाव में अपनी शर्मनाक हार नहीं पचा पाने की वजह से ही बीजेपी यह सब कर रही है. राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैली हिंसा में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों ने भी आग में घी डालने का काम किया है. रविवार रात से ही ऐसे सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो टीएमसी की कथित गुंडागर्दी के दावों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें कहीं दफ्तरों को जलते दिखाया गया है तो कहीं दुकान या मकानों में लूटपाट के दृश्य हैं. एक वीडियो में तो कुछ युवक दो महिलाओं को बाल पकड़ कर बड़ी बेरहमी से खींचते और उनको मारते नजर आते हैं. महिलाओं की पिटाई वाला वीडियो कहाँ का है, यह साफ नहीं है. बीजेपी के नेता या पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

मिसाल के तौर पर बीजेपी की ओर से इंडिया समूह के एक पत्रकार अभो बनर्जी की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट में उसे कूचबिहार जिले के शीतलकुची में हिंसा में मृत मानिक मैत्र बताया गया. लेकिन उस पत्रकार ने जब इसे फर्जी बताते हुए अपने जिंदा होने का दावा किया तो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया. रविवार की हिंसा के बाद सोमवार को बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि टीएमसी के लोगों ने बीरभूम जिले के नानूर में पार्टी की दो महिला चुनाव एजेंटों के साथ सामूहिक बलात्कार और मारपीट की है. बीजेपी नेता सौमित्र खान ने राजीव राय नामक यूजर के हैंडल से किए गए ट्वीट को री-ट्वीट किया है. ठीक यही ट्वीट बीजेपी की महिला नेता अग्निमित्र पॉल ने भी किया है. लेकिन खान के रीट्वीट में जहां इसे एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां बताया गया है वहीं अग्निमित्र ने इसे नानूर में गेंगरेप वाले ट्वीट से जोड़ा है. लेकिन मंगलवार शाम को उनमें से एक महिला ने

टीएमसी के जिला अध्यक्ष अणुब्रत मंडल के दफ्तर में बैठकर पत्रकारों से कहा, मेरे साथ ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर इस बारे में फर्जी खबरें पोस्ट की जा रही हैं. मुझे नहीं पता किसने यह झूठी खबर फैलाई है. बीरभूम के पुलिस अधीक्षक नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी कहते हैं, "सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली यह खबर झूठी और निराधार है. एक राजनीतिक पार्टी के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी की दो महिला एजेंटों के साथ सामूहिक बलात्कार का जो दावा किया है वह पूरी तरह फर्जी है. हम ऐसी पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे."

शिवसेना की टिप्पणी

शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हिंसा से राजनीति का 'रक्तंजित' रूप उजागर हुआ है और यह दिखाता है कि लोकतंत्र के बजाए ताकत तथा बाहुबल का शासन कायम है. पार्टी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार दोनों पर समान रूप से है.

पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में कहा है, "पश्चिम बंगाल में वास्तव में क्या हो रहा है और इसके पीछे किसके अदृश्य हाथ हैं? ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए. जब से राज्य में बीजेपी हारी है हिंसा की खबरें आ रही हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट की. लेकिन यह सब दुष्प्रचार है." इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए 17 लोगों में नौ बीजेपी से जुड़े लोग थे, बाकी टीएमसी के कार्यकर्ता थे. इसका मतलब है कि दोनों पक्ष इसमें शामिल हैं. संपादकीय में कहा गया है कि इस हिंसा के विभिन्न पहलुओं से साफ है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है.

आरएसएस का बयान

अब चुनावी नतीजों और हिंसा के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भी इस मुद्दे पर मुंह खोला है. आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बंगाल हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा, राज्य सरकार से मांग की है कि हिंसा को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं. पश्चिम बंगाल पुलिस ने फर्जी खबरों और वीडियो-तस्वीरों से निपटने के लिए एक अलग साइबर सेल का गठन कर हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी जारी किया है. अब तक दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और कम से कम आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

राजनीतिक पर्यवेक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास तो पुराना है. लेकिन इस बार जिस तरह इस हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है वह खतरनाक है. इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए ठोस पहल जरूरी है."

रूपा तिर्की मामले में आदिवासी अधिकार मंच ने सीएम को भेजा पत्र

<https://www.livehindustan.com/jharkhand/ranchi/story-tribal-rights-forum-sent-letter-to-cm-in-rupa-tirki-case-4018491.html>

आदिवासी अधिकार मंच ने सीएम को पत्र लिखकर साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में मंच के प्रफुल्ल लिंडा, सुखनाथ लोहरा, आलोका, वीणा लिंडा, अनिमा मुंडा ने केंद्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पत्र भेजा है। पत्र में आरोप लगाया गया कि यह घटना पुलिस प्रशासनिक और असामाजिक तत्वों के सांठगांठ के किया गया है। ऐसी घटना से आदिवासी समाज आक्रोशित व विक्षुब्ध है। इसलिए पूरे घटना क्रम की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जानी चाहिए।

माले ने निर्मल मिंज और रूपा तिर्की को दी श्रद्धांजलि

रांची। भाकपा माले ने शुक्रवार को डॉ निर्मल मिंज एवं मृत दारोगा रूपा तिर्की को श्रद्धांजलि दी। दो मिनट की मौन धारण के बाद सर्वप्रथम राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने मिंज की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए माले केन्द्रीय कमिटी सदस्य शुभेंदु सेन ने कहा की डॉक्टर निर्मल मिंज सिर्फ बिशप नहीं बल्कि आदिवासी सामाज में वाम प्रगतिशील विचारों के भी वाहक थे। जन संस्कृति मंच के अध्यक्ष जेवियर कुजूर ने कहा कि झारखण्डी भाषा, साहित्य और संस्कृति को स्थापित करने में डॉ० निर्मल मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे 1970 के दशक में तरंग भारती से जुड़कर और दर्जनों पुस्तक लिखकर झारखंड आंदोलन को नई दिशा देने का काम किए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद और जिला सचिव भुवनेश्वर केवट ने भी संबोधित किया।

Covid-19: Why India should vaccinate refugees and undocumented immigrants as well

<https://scroll.in/article/994207/covid-19-why-india-should-vaccinate-refugees-and-undocumented-immigrants-as-well>

Riyaz*, a Rohingya refugee who lives in a crowded camp in Delhi along with nearly 300 others, is desperate to get himself vaccinated against Covid-19. But India's ongoing vaccination drive is only open to its own citizens or those with any of the 11 identity documents specified by the government.

All that Riyaz and the others in the camp have are the refugee cards issued by the United Nations High Commissioner for Refugees. "A few of us tried to get vaccinated but we were asked for Aadhaar cards," he told IndiaSpend. The lack of an Aadhaar card also means that refugees cannot get themselves tested for Covid-19.

Most people were able to earn Rs 500- Rs 700 a day earlier to support their family, but now they are not able to find any work. "We need free vaccination because we cannot afford to pay," he said.

Durgaram Sharma, 36, is a Nepalese security guard in an east Bengaluru apartment complex who has been living and working in India for 17 years. He has an Aadhaar card and can seek a vaccine in India but not his wife, Bindu, who has none of the requisite identity papers.

India's newly liberalised vaccine policy makes all its adult citizens eligible, but makes no mention of the undocumented immigrants and refugees who live and work here: India currently has more than 2,40,000 refugees and asylum seekers and nearly 38 lakh Nepali and Bangladeshi immigrants.

In 2019, 95.3% of India's immigrants originated in the same Sustainable Development Goal region (as per the United Nations' classification for its SDG Goals programme – Central and Southern Asia, the latter comprising neighbouring countries such as Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Afghanistan). This number has not changed significantly from 1990 (96.8%), IndiaSpend reported in January 2021.

At a time when Indian citizens are facing difficulties due to vaccine shortages, the high cost of getting vaccinated in a private facility and glitches in the online registration and scheduling system, the lack of clarity in the official policy could leave millions of non-citizens out of India's vaccination drive, humanitarian groups warn. This could also endanger the health and lives of India's citizens and hamper its efforts to curb the pandemic, they add.

"The right to health is part of the right to life. If there are requirements for specific documentation, a large number of people will fall out of the vaccination process and face death," said Ravi Nair, executive director, South Asia Human Rights Documentation Centre, a human rights network.

'Accept refugee documents'

Salai Cung Dawt, a Chin refugee from Myanmar and a community leader and coordinator for the Chin Human Rights Organisation, is worried for his people in India. There are nearly 3,000 Chins in Delhi and most work in the informal sector earning between Rs 10,000 and Rs 15,000 monthly. Those who tried to register online are unable to because they do not have government identity cards, he said.

Many Rohingya refugees in India work as labourers, drivers, or at odd jobs. While they received support like essential items and medicines from the government and other multilateral agencies during the 2020 lockdown, that has not been the case during the current surge, said Riyaz. "It has been difficult to even keep our fast during the holy month of Ramzan."

Dawt, who is in India since 2008, has approached the UNHCR to resolve the question of documentation for the vaccine. "We coordinate with UNHCR for our needs and are yet to hear from them on Covid-related information," he said. "If they [India] include UNHCR cards for registration, it will be helpful for us."

UNHCR India declined to comment on India's specific strategy but reiterated its global position that it advocates for the inclusion of refugees and asylum-seekers in national vaccination plans, in line with other government criteria.

Chin refugees need access to free vaccine doses because they cannot afford private ones, Dawt told IndiaSpend.

"The government must provide universal vaccination to anyone in India. Anyone can transmit the disease," said Nair. "Vaccination cannot be restricted to citizens."

Nearly 20 countries are known to have begun inoculating refugees and this includes Nepal, Jordan and Rwanda, said an April 7 UNHCR report. "In many parts of the world, actual immunisation remains a challenge, largely due to the unequal availability of vaccines and the capacity of health systems," it added.

In Greece, immigrants are falling out of the vaccination net because its inoculation drive is linked to social security numbers.

India contributed \$10 million to the SAARC Covid-19 Emergency Fund, to supply essential drugs, medical consumables, Covid-19 protection and testing kits, and other equipment. The press release did not specify vaccination plans.

"We are ready to contribute to the quest for a vaccine; to make any such candidate vaccines at mass scale and at affordable price points," said Sanjay Bhattacharya, secretary (Consular, Passport, Visa and Overseas Indian Affairs) in July 2020.

The Ministry of External Affairs refused to comment on the issue of including refugees in the immunisation drive. "Ministry of External Affairs is not the nodal ministry for the

vaccination policy therefore I would request you to contact the Ministry of Health,” said Yatin Patel, officer on special duty (PR), Ministry of External Affairs, in response to IndiaSpend’s queries on the government’s strategy for vaccinating immigrants and refugees.

IndiaSpend has written to and shared multiple reminders with the Ministry of Health and Family Welfare for its response. We will update the copy if and when they respond.

Seasonal migrants

Seasonal immigrants from Nepal are likely to face a bigger problem securing vaccination in India because they are not entitled to Aadhaar cards or other government-issued identity documents. Migration to India from Nepal is largely seasonal, with workers spending nearly nine months before returning home, as per a 2017 World Bank report.

“These seasonal migrant workers fall outside of the ambit of any documentation in India, especially the Aadhaar card [since they cannot fulfil the residency criteria],” said Chitra Rawat, research assistant at India Migration Now, a migration research organisation. There are different drives initiated by the state governments for internal migrants and similar drives can be undertaken for immigrant workers as well, she added.

With a face shield strapped to his face and a mask to cover his nose and mouth, Durgaram Sharma, 36, is doing his evening rounds at an east Bengaluru apartment. He deals with nearly 100 residents and at least 10 vendors daily and his work leaves him – and his family – vulnerable to Covid-19.

Sharma, a Nepali who has been working in India for 17 years now, has an Aadhaar card that theoretically allows him access to the vaccine. But his wife Bindu would still be denied a jab. “It costs nearly Rs 7,000 to go back to Nepal, and borders are sealed,” he said. “We cannot.”

An Aadhaar number is not a proof of citizenship, UIDAI had confirmed in February 2020. It can be obtained by any resident who has been in the country for 182 days over the previous 12 months from the date of enrolment.

On a monthly salary of Rs 10,000, Sharma said he could not afford vaccination from a private facility, where the charges range between Rs 600 and Rs 1,200. Since the pandemic broke, Sharma’s wife has not been able to find a job as domestic help.

“Across the world, the International Labour Organization advocates towards ‘vaccination for everyone’ including immigrant workers,” said Shabarinath Nair, regional migration specialist at the ILO Decent Work Team for South Asia, which looks at policies on productive and fair employment. “Any lack of documentation should not restrict vaccination of any migrant worker, as it will potentially risk the remaining population. We strongly recommend governments to consider these aspects.”

India is estimated to have more than half a million Nepali immigrants in India, mostly daily wage earners. The number could be as high as 3 million, according to The Kathmandu Post. Nepali migrants do not need work permits to find employment due to the open border ties between the two countries.

India also receives Bangladeshi immigrants and in 2010 they constituted the single largest group (32 lakh) of international migrants in the global south, according to the United Nations. A more recent estimate from the think-tank Carnegie India, from 2016, put the number at 1.5 crore.

During the Covid-19 surge in 2020, the Nepal government refused to allow Nepalis living in India to return home and this was a violation of human rights, said Nepal's August 2020 National Human Rights Commission report, Rights of Migrant Workers in the Clutches of Covid-19 Pandemic. Again, in May, the Nepal government decided to close 22 border points due to the pandemic surge in India and warned of the lack of hospital beds and vaccine shortages in Nepal. On April 26, Bangladesh too sealed its borders with India for two weeks over Covid-19 concerns.

"Migrants are met with different barriers like no targeted outreach to meet their specific healthcare needs, or facilitation to access Indian healthcare system," said Rawat.

In providing vaccination to migrants, no special eligibility conditions for identity cards or other documents should be insisted on as many are unlikely to possess documents, said R Ramakumar, economist, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. "To remove all forms of vaccine hesitancy on the part of migrants, this is very important. Further, it is also important that we provide vaccination free of cost to all migrants," he said.

International migrants in India face many obstacles to integration, and the country ranked last among 52 countries ranked on the Migrant Integration Policy Index 2020. The index measures policies to integrate migrants in countries across five continents. Health along with anti-discrimination policies and political participation policies emerged as "particularly unfavourable" barriers for integration, it added.

Private vaccination unaffordable

A few lanes from Durgaram Sharma's worksite, Hariprasad Joshi, 51, a Nepali from Kailali district, too works as a security guard. Joshi, who moved from Maharashtra's Ratnagiri district to Bengaluru seven years ago, has made three failed attempts to get vaccinated – twice at a government clinic and once at a private hospital.

"They told me that it was full and I would have to come back later," said Joshi. "I cannot afford to stay away from work as a security guard. I'll lose my job." The sole earner in the family, Joshi lives with his wife and daughter in a tiny room in the building where he works, earning Rs 9,000 a month.

"Failing to take migrants into account in our vaccination efforts would hamper the effectiveness of these campaigns and make it difficult to end the pandemic," said an

April 23 blogpost from the International Organisation for Migration, an UN-related organisation.

Ganga, a domestic help from Nepal's Kanchanpur, has yet to register for the vaccine and has no clear idea how to get herself vaccinated. Her younger brother, Basu, pointed out that most of the immigrant fraternity lives on daily wages and cannot afford to pay for the vaccines. "All those who know how to register online can manage, but what about the poor who have no information or do not understand the language or process?" he asked.

Basu is already in debt after paying Rs 3,500 for his pregnant wife's medical-check up at a private clinic, he said. "She cannot find work, and I get Rs 10,200 a month," he said. "We cannot afford more than Rs 200 or Rs 220 for a dose, after borrowing cash." If it is not provided for free, he would be forced to go without vaccination, he said.

Gujarat: Civil told to pay Rs 60,000 over lack of discharge summary

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/civil-told-to-pay-rs-60k-over-lack-of-discharge-summary/articleshow/82467808.cms>

A consumer court has ordered Civil Hospital, Ahmedabad, to pay Rs 60,000 compensation to a patient's relatives because the hospital failed to provide a discharge summary when the patient left the hospital. The Gujarat State Consumer Dispute Redressal Commission said the hospital did not provide a discharge summary to the patient and in the absence of this important medical paper, the patient and his family could not obtain expert advice. This was considered a deficiency in service and Rs 60,000 compensation was considered apt to meet the end of justice. Besides, the hospital authorities will have to pay Rs 10,000 to relatives of the patient for legal expenditure. The litigation was initiated by Natwar Chavda's wife, Laxmi, and mother, Chancharben, with help from the Consumer Education & Research Society in 2008. The complaint was filed with the consumer forum of Ahmedabad district after Chavda suffered paraplegia following a surgery at Civil Hospital for removal of a kidney stone in July 2005.

Chavda remained hospitalized from July 25 to February 2006 after the surgery, which left him paraplegic. He later passed away and his family members sued the hospital and the doctor who conducted the surgery, alleging medical negligence. The Consumer Dispute Redressal Forum, Ahmedabad district did not accept that there was medical negligence on the part of the doctor and dismissed the complaint.

The family appealed before the commission and asserted that this was a case of medical negligence, but this contention was not accepted by the commission. However, the commission accepted the family's argument that without the discharge summary, it was difficult for the patient to get expert medical advice. It said that the Medical Council of India has imposed an obligation on hospitals with a 2002 notification to maintain medical records and provide patients access to them. Besides the MCI notification, the consumer court also cited NABH and NHRC guidelines and cited observations of the Bombay high court to say that it is crystal clear that it is the duty of the hospital and the doctor to provide the discharge summary and medical papers within 72 hours of discharge.

रिटायर फौजी की पिटाई का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दाह संस्कार को जा रहे सिख पूर्व सैन्य कर्मी की पुलिस पिटाई का मामला तूल पकड़ गया है। इस घटना से सिख समुदाय बेहद आहत है। अब अधिवक्ता सनप्रीत सिंह ने इस घटना से संबंधित वीडियो समेत अन्य सबूतों के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायती पत्र भेजा है। उन्होंने



के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

शुक्रवार को हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता सनप्रीत आजवानी ने आयोग के चेयरमैन व सदस्यों को पत्र भेजकर कहा कि तीन रिटायर सैन्य कर्मी रेशम सिंह अपनी 80 साल की बुजुर्ग मां के साथ था। आरोप है कि पूरनपुर मंडी गेट पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही वाहनों की जांच के दौरान रेशम सिंह व पुलिस कर्मियों की बहस हुई। पुलिस का आरोप था कि रेशम सिंह द्वारा पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ी गई और रेशम सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। सनप्रीत के अनुसार इंटरनेट मीडिया में मौजूद घटना के वीडियो से साफ है कि पुलिस ने रेशम सिंह के साथ अत्याचार किया। कहा कि रेशम सिंह सिख समुदाय से हैं, पुलिस द्वारा उनकी पगड़ी का भी अपमान किया गया। जिस कारण सिख समुदाय में नाराजगी है। पुलिस द्वारा रिटायर सैन्य कर्मी के साथ थर्ड डिग्री का प्रयोग किया गया। उन्होंने आयोग से इस प्रकरण का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

NHRC seeks ATR from Cuttack SP on minor's rape

POST NEWS NETWORK

Bhubaneswar, May 7: The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Cuttack Superintendent of Police (SP) to submit an action-taken report (ATR) in connection with the alleged sexual abuse of a minor girl.

The SP has been instructed to submit the ATR within six weeks of the receipt of the order of the apex rights panel. The NHRC gave the direction while hearing a complaint filed by activist Himanshu Sekhar Nayak on the basis of a news report published in Odia daily Dharitri.

According to the report, the family members of a high school student

lodged a complaint with Mahanga police alleging that a distance relative of the victim who used to visit their house had sexually abused the girl repeatedly for over a month in Mahanga area of Cuttack.



Family members of a schoolgirl lodged a complaint with Mahanga police alleging that a distant relative had raped the minor repeatedly

However, the local police did not register a case nor did it take any action on their complaint.

The elder sister of the girl has recently warned of committing suicide near the police station over the alleged apathy of Mahanga police.